

मजदूर मोर्चा

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

पाक्षिक

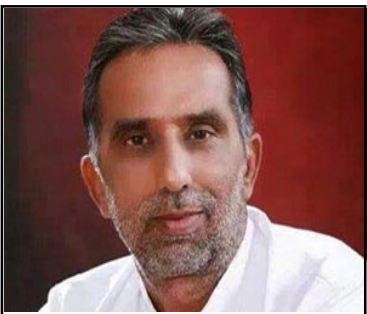
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

वर्ष 31 अंक 2 फरीदाबाद 1-15 दिसम्बर 2017 फोन : - 9999595632 ₹ 2

- डीईआईसी यानी स्कूली बच्चों के साथ किया जा रहा है मजाक	3
- रेप-अपराधी को बचाने का प्रयास किया डा. संगीता अग्रवाल ने, पॉक्सो नदारद	4
- दिल्ली विश्वविद्यालय का दयाल सिंह कॉलेज (सांध्य) बना वन्दे मातरम् का अखाड़ा	5
- वरुण श्योकंद की पहल पर एनजीटी ने बिल्डरों पर लगाया जुर्माना	8

मोदी की गोदी में जाने को आतुर 'जनसत्ता' सम्पादक मुकेश भारद्वाज की पेड न्यूज फ़रीदाबाद में झूठे वादों का डंका बजाते मंत्री कृष्णपाल का प्रायोजित साक्षात्कार

मजदूर मोर्चा ब्यूरो फ़रीदाबाद दिल्ली के कभी बुद्धिजीवी वर्ग में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दैनिक 'जनसत्ता' के 19 नवम्बर अंक में फ़रीदाबाद के सांसद एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गूजर का, बिके सम्पादक मुकेश भारद्वाज ने सात का साक्षात्कार पैनल बना कर एक प्रायोजित साक्षात्कार छपा है। इस दैनिक की शहर में आती ही 91 प्रतियां आती हैं, इसलिये मंत्री जी ने अपने पल्ले से 500 प्रतियां विशेषतौर पर मंगवा कर शहर में मुफ्त बंटवाई।



नमो... नमो... नमो...

विदित है कि ऐसे प्रायोजित साक्षात्कार में पत्रकार वही सवाल पूछते हैं जो मंत्री जी चाहते हैं; यानी कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनसे वह असहज एवं निरुत्तर होते हैं। इसलिये वास्तविक साक्षात्कार से ऐसे नेता बचते हैं। लेकिन जनता के बीच अपनी छवि चमकाने के लिये इस तरह के प्रायोजित साक्षात्कार छपवाते हैं। लगभग पूरे पन्ने पर छपे इस साक्षात्कार में चार जगह तो मंत्री जी की बड़ी-बड़ी सुंदर तस्वीरें हैं। लेकिन उनसे पूछे गये न तो सवाल किसी काम के हैं न ही जवाब। सात पत्रकारों द्वारा लिये गये इस साक्षात्कार में किसी ने यह नहीं पूछा कि 15 अगस्त 2014 को यमुना तट पर मंशावली

गांव में शिलान्यास का क्या ड्रामा था? विधान सभा चुनाव से पूर्व केन्द्रीय सड़क मन्त्री नितिन गडकरी द्वारा यमुना पुल का शिलान्यास कराने के नाम पर भारी भीड़ एकत्रित की गयी थी। गत 25 वर्ष में दूसरी बार हुए इस शिलान्यास के वक्त जनता को बताया गया था कि केवल 2 वर्ष में इस पुल से आवागमन शुरू हो जायेगा। लेकिन आज तक वहां एक ईंट नहीं लगी, ईंट तो क्या लगनी थी, यह तक नहीं पता कि पुल बनाने का सौदा गडकरी ने किससे किया है। मंत्री जी से किसी पत्रकार ने यह भी नहीं पूछा कि गत 8 सालों से दिल्ली-पलवल के बीच बन रही चौथी लाइन

क्यों अटकी पड़ी है? फ़रीदाबाद ओल्ड रेलवे स्टेशन की अधबनी इमारत जो गत 5 बरसों से खड़ी है उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? ठेकेदारों के 250 करोड़ की पेमेंट रोक कर क्यों उन्हें भागने पर मजबूर किया जा रहा है? दिल्ली-पलवल के दैनिक यात्रियों की जो दुर्दशा कांग्रेस राज में थी, उससे भी बदतर अब भाजपा राज में क्यों कर दी गयी है? क्या इसका समाधान भी 2022 के एजेंडे में है? माननीय मंत्री जी से किसी वरिष्ठ पत्रकार ने यह भी पूछने की जहमत नहीं उठाई कि शहर के बीचों-बीच चल रहे राजमार्ग के काम के नाम पर शहर की जनता को क्यों बंधक बना कर रखा गया? विदित है कि करीब 7 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार ने देश के एक बड़े पूंजीपति अनिल अम्बानी की रिलायंस कम्पनी को लूट का यह ठेका दिया था। उसके बाद आई डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन) ने कब का अपना काम पूरा करके जनता को बड़ी सुविधा प्रदान कर दी। लेकिन अम्बानी की चोर कम्पनी जनता से टोल वसूली के लिये तो एक के बाद एक टोल बैरियर बनाती जा रही है लेकिन अपने जिम्मे लिया काम पूरा करने की उसे कोई चिन्ता नहीं। एक के बाद एक दर्जनों डेड लाइन (काम पूरा करने की तिथि) निकलती जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं।

प्रद्युमन हत्या कांड में अशोक कभी न्याय नहीं पायेगा

पुलिस ने टार्चर किया, अदालत ने असंवेदनशीलता की हद पार की

गुडगांव (म.मो.) असली हत्यारे को ढूंढ पाने में असफल पुलिस ने आसान शिकार समझ कर मौके पर मौजूद बस कंडक्टर अशोक को ही दबोच लिया। टार्चर की सभी मानवीय हदें पार करते हुए उसे हत्या कबूलने पर मजबूर कर दिया। सीबीआई जांच ने एक झटके में ही गुडगांव पुलिस की पोल खोलते हुए अशोक को बेगुनाह बता दिया। हालांकि, तब भी अदालत से अशोक का डिस्चार्ज यानी तुरंत रिहाई नहीं मांगी। इसके बावजूद, उसे जेल भेजनेवाली अदालत ने भी उसे तुरन्त रिहा करने की कार्यवाही की बजाये दो सप्ताह से अधिक जेल में डाले रखा; छोड़ा भी पूरा अदालती ड्रामा करके जमानत की कड़ी शर्तों पर। बेगुनाहों का टार्चर करने व मानवाधिकारों का हनन करने में पुलिस तो बदनाम है ही, लेकिन इसके लिये अदालतें कहीं बड़ी ज्यादा जिम्मेदार हैं जो पुलिस के इन अमानवीय गुनाहों पर पर्दा डालने का काम करती हैं।

टार्चर के बाद, 'कबूलनामे' के साथ जिस टूटी-फूटी हालत में पुलिस ने अशोक को अदालत में पेश किया तो क्या अदालत की आंखें फूटी पड़ी थीं? तमाम संवेदनायें मर चुकी थीं? यदि न्यायिक मैजिस्ट्रेट की थोड़ी बहुत भी मानवीयता एवं संवेदना अदालत में होती तो वह तुरंत मेडिकल बोर्ड द्वारा अशोक के मेडिकल परीक्षण का आदेश देती और इलाज कराने हेतु अस्पताल में दाखिल कराती। इसके साथ-साथ टार्चर के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का आदेश देती।

इसके विपरीत अदालत ने पुलिस के प्रति चिर परिचित वफ़ादारी निभाते हुए अपनी आंखें मुंदे रखीं और पुलिस की 'आज्ञा' का पालन करते हुए उसे जेल भेज दिया। जाहिर है वहां उसकी हालत और बिगड़ती चली गयी क्योंकि जेलों में तो वैसे ही 'न्याय' के शिकंजे में फंसे इन्सान को इन्सान समझने और उसका इलाज कराने की कोई व्यवस्था नहीं होती।

आज राष्ट्रीय मीडिया बार-बार अशोक की दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है; अदालत में भीतर जाने से पूर्व भी तो मीडिया ने उसे देखा था, तब क्यों चुप्पी साधे रखीं? हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जो बात-बात पर अपनी संवेदना दिखाते हुए स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर देते हैं, इस मामले में उन्हें क्यों काट मार गया है? क्यों नहीं ये न्यायालय जघन्य मामले इसका संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही का आदेश देते?

पूर्व उपायुक्त प्रवीण की पत्नी ने हवाई अड्डे पर थप्पड़ मारा और खायी

नई दिल्ली (म.मो.) फ़रीदाबाद के पूर्व उपायुक्त प्रवीण कुमार की पत्नी अहमदाबाद जाने के लिये दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर दिनांक 28 नवम्बर को प्रातः 4 बजकर 18 मिनट पर पहुंची। उनकी फ्लाइट का समय था 5 बजे का। नियमानुसार उन्हें 4.15 से पहले बोर्डिंग कार्ड पर पहुंचना चाहिये था क्योंकि फ्लाइट टेकऑफ से 45 मिनट पहले कार्डेटर बन्द कर देने का आदेश है।

अब श्रीमती जी ठहरी एक आईएसएस की पत्नी, वह भी प्रवीण कुमार की; उलझ गयी एयर इंडिया के काउंटर कर्मचारियों से। होते-होते मामला पहुंचा अड्डा मैनेजर के पास। इत्फ़ाक से वह भी एक निकली थाकड़ महिला। एक आईएसएस की पत्नी होने के नाते, गर्मा-गर्मी के बाद नौबत आ गयी मार-पीट की। प्रवीण की पत्नी ने गुस्से में एक थप्पड़ जड़ दिया शेष पेज दो पर

गूजर का मोदी गान

आज किसी भी उल्लू बनाने वाले राजनीतिक दल की भाँति भाजपा में भी पद पर बने रहने हेतु शीर्ष नेताओं का गुणगान एवं चापलूसी अनिवार्य है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के इरादे से सांसद एवं मंत्री कृष्णपाल ने अपना साक्षात्कार 'जनसत्ता' में छपवाया है, साथ में स्थानीय जनता के बीच जो छवि बनती है वह बोस में।

साक्षात्कार में मोदी का गुणगान करते गूजर जी फर्माते हैं कि उन्होंने फ़रीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनवा दिया। शहर कैसा स्मार्ट बना है उसे शहर भर में सड़ते गंदगी के ढेरों, उफ़रने सीवरों, घूमते आवारा पशुओं, अवैध निर्माणों एवं कब्जों के चलते लगने वाले जाम, स्कूलों व अस्पतालों की दुर्दशा आदि से बखूबी समझा जा सकता है।

गुडगांव में कौन सा विकास हो गया जिससे फ़रीदाबाद की तुलना गूजर ने की है, हां विकास की घोषणाओं में कोई कमी नहीं। जाट आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार ने जिस तरह से जातीय वैमनस्य पैदा किया वह जग जाहिर है। इस काम के लिये भाजपा ने बाकायदा अपने एक सांसद राजकुमार सैनी को तैनात कर दिया। इसी के परिणामस्वरूप राज्य भर में भयंकर दंगे हुए।

फ़रीदाबाद में बड़ी योजना लाने के नाम पर मंत्री जी के पास केवल यमुना पुल, चौड़ा होता राजमार्ग, रेलवे स्टेशन की अधबनी इमारत, पक्की सड़कें व स्वच्छता अभियान के अलावा कुछ था तो "कांग्रेस के 60 सालों में बिगड़ा हाल सुधारने में समय तो लगेगा" वाला जुमला ही था।

नोटबंदी से हुई लोगों की दुर्गति को देखने के लिये मंत्री जी ने मोदी की स्टार्ट-अप योजना का उल्लेख किया और मोदी की तरह ही झूठ बोलते हुए करोड़ों को रोजगार मिलने की बात कही। रेल सेवा की बंद से बदतर हालत के जवाब में वे हास्यास्पद दावा करते हैं कि रेल मंत्री को ट्वीट करते ही जवाब मिलता है, बाकी, 3 साल में इससे अधिक और किया भी क्या जा सकता है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बराला के पुत्र द्वारा लड़की छेड़ने के बाबत मंत्री जी कहते हैं कि कनून अपना काम कर रहा है। कानून तो अपना काम तब करेगा ना जब उसे सत्ताधारी करने देंगे। घटना वाली रात बराला पुत्र को थाने से छुड़वाने जो भाजपाई नेता गये थे वे क्या कानून की मदद करने गये थे? यदि लड़की पक्ष मजबूत न होता तो कानून बेचारा क्या कर पाता?

मोदी...मोदी...मोदी...से पूरे पेज का साक्षात्कार भरा पड़ा है।

'सुरक्षित' सीट ढूँढते खट्टर की निगाहें एनआईटी पर

मजदूर मोर्चा ब्यूरो करनाल

तीन साल हरियाणा पर राज कर चुके मनोहर लाल खट्टर को अब दो साल बाद होने वाले चुनावों की चिन्ता सताने लगी है। यदि भाजपा आला कमान ने मई 2019 में होनेवाले लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा विधान सभा के चुनाव भी कराने का निर्णय ले लिया तो दो साल का यह समय और भी घट जायेगा।

देश के बड़े पूंजीपतियों के मीडिया रथ पर सवार नरेन्द्र मोदी की बनी लहर के एक ही उछाल में खट्टर विधायक भी बन गये और मुख्यमंत्री भी। यानी एकदम जीरो से फुल हीरो। विधानसभा का चुनाव लड़ने की न तो इनमें कोई लियाकत थी और न ही इनके पास कोई क्षेत्र। गृह जिला रोहतक होने के बावजूद इनकी वहां कोई पहचान कभी नहीं रही। पहचान तो करनाल में भी नहीं थी, लेकिन करनाल को रोहतक जिले की अपेक्षा नरम क्षेत्र समझा गया। क्षेत्र की नरमी जालंधर से आये अश्वनी चोपड़ा ने लोकसभा चुनाव जीत कर सिद्ध कर ही दी थी। यह सब भाजपा एवं मोदी का करिश्मा माना गया। इसी करिश्मे के बल पर खट्टर को भी करनाल से विधायक चुनवा लिया गया।



मनोहर लाल खट्टर : सोई सरकार, सुरक्षित सीट!

दरअसल करिश्मा भी क्या था, जनता कांग्रेसी कुशासन से बुरी तरह निराश व परेशान हो चुकी थी। ऐसे में एक कुशल मदारी की भाँति मोदी जनता को बरगलाने में कामयाब हो गये और अपने चुनावी जुमले जनता को बेच दिये। विधान सभा चुनाव बाद कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा, इसे गुप्त रख कर अहीरवाल में राव इन्द्रजीत को, जाटों में कैप्टेन अभिमन्यु को, ब्राह्मणों में रामबिलास शर्मा को उत्तर हरियाणा में अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाने के सुरें भाजपाई आला कमान छोड़ती रही। यदि कहीं खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी गयी होती तो भाजपा का बंटोधार हो जाता।

निकल गयी तो भाजपा बल्कि संघ ने अपनी मनमानी करते हुए खट्टर के रूप में खोटा सिक्का हरियाणावी जनता के मत्थे मढ दिया। वैसे यह भी हो सकता है कि पूरे भाजपा विधायक दल में बाकी सिक्के इससे भी अधिक खोटे हों और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आला कमान ने खट्टर को ही बेहतर समझा हो।

अपने तीन साल के शासनकाल में खट्टर ने पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि न तो इनमें कोई राजनीतिक सूझ-बूझ है और न ही प्रशासनिक। हो भी कैसे सकती है, जब इन्होंने सारी उग्र आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) की 'पढाई' का प्रचार शेष पेज दो पर

एक बार जनता के हाथ से बात